के साथ लघु उद्योग खोले जाएं तो उनसे इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सकेगा और स्थानीय लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिल सकेगा ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में समुचित कदम उठाये ।

(iv) NEED FOR EXTRA ALLOTMENT OF CEMENT TO ORISSA FOR WORKS TO CONTROL FLOODS.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Quarterly allocation of cement to Orissa has been reduced from 1,23.400 M.T. in the first quarter of 1980 to 81,400 M.T. in the fourth quarter of 1980. Several bridges and culverts were washed away. Most of the public and private buildings in the flood-affected areas were seriously damaged. For flood restoration work, at least *ad hoc* allocation of cement to Orissa is urgently needed. I urge upon the Government to direct the Cement Controlled to allot extra quantity of cement to Orissa urgently for flood restoration work, and not to curtail the allotment of cement to Orissa from the two cement factories of the State. as the landing cost of Andhra cement is much more at places like Puri and Cuttack.

(v) DRINKING WATER PROBLEMS OF PATNA CITY

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, "पटना में पेय जल संकट" । पटना नगर बिहार की राजधानी है । चल रहे जनगणना अभियान के बाद उसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो जाने का अनुमान है । शहर का विकास भी तेजी के साथ हो रहा है ।

नगर के विकास के साथ-साथ उसकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं जिनके निराकरण की ओर सरकार का ध्यान या तो आकृष्ट नहीं हो पा रहा है या धनाभाव के कारण वह कुछ कर सकने में असमर्थ है । समस्याओं में पेय जल का संकट सब से बड़ी समस्या है । नहाने-धोने की बात तो दूर रही पीने के लिए भी लोगों को पानी नहीं मिलता । गर्मी के दिनों में तो नागरिकों में कुहराम मच जाता है और लोगों को पानी की तलाश में दूर-दूर का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पाता । कभी कभी तो विरोधस्वरूप घड़ा फोड़ो अभियान भी चल पड़ता है ।

बांकीपुर और पटना सिटी दोनों क्षेत्रों के दर्जनों मुहल्लों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है । इसका कारण आर्थिक है । धन के अभाव में बड़े बड़े नलकूप और टंकियों की व्यवस्था नहीं हो पाती । पटना वाटर बोर्ड ने इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार से साढ़े चार करोड़ रुपये की मांग की है । राज्य सरकार ने इसके लिए भारत सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है । मेरा अनुरोध होगा कि पटना नगर में जल की व्यवस्था के लिए सरकार को शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार को मदद भेजनी चाहिए ताकि पेय जल की उचित व्यवस्था की जा सके ।

(vi) NEED FOR STEPS FOR IMPLEMENTATION OF PALEKAR AWARD

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, पालेकर न्यायाधिकरण की घोषणा हो जाने के बावजूद भी अभी तक बड़े-बड़े अखबार उससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय काम में ला रहे हैं । अगर सरकार के द्वारा इसे अविलम्ब लागू करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में इनके लागू करने के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायेगी । संवाददाताओं के विभिन्न संगठनों ने भी इस प्रकार की मांग का समर्थन करते हुए त्रिपक्षीय समिति बनाने की मांग की है । जिसमें अखबार व समाचार एजेन्सियों के संवाददाताओं के प्रतिनिधि, अखबारों के प्रबंधक के प्रतिनिधि व केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों । जो पालेकर एवार्ड के न्यायसंगत क्रियान्वयन को देख सकें क्योंकि जब से इस एवार्ड की घोषणा हुई है बड़े बड़े अखबारों ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों में डालना प्रारम्भ कर दिया है। इसके शिकार विशेष रूप से अंशकालिक संवाददाता हो रहे हैं जो इन अखबारों में 20-25 वर्ष से कार्य करते आ रहे हैं ।